Year	Gold seized throughout the country		Gold seized in the jurisdiction of the Customs (Preventive) Collectorate, Gujarat.	
	Quantity (in Kgs.)	Value (in crores)	Quantity (in Kgs.)	Value (in crores)
1987	2255	65.78	13.029	0.37
1988*	6094	200.51	164.657	50.40
1989* (upto 28-2-1989)	1832	61.00	54.15	18.72

* Figures are provisional.

However, since smuggling is a clandestine activity, it is no feasible to estimate the quantum of gold that is being smuggled into the country across the Gujarat and Saurashtra coasts. The increase in seizures need not necessarily indicate a spurt in smuggling of gold and could be due to the intensified drive against sumggling. The Gujarat and Saurashtra coasts continue to be vulnerable to smuggling of gold because of close proximity to Dubai.

Instructions to Ministries to cut down expenditure

1714. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether strict instructions have been given to all Central Ministries to keep down their expenditure within the budgeted level; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): (a) Yes, Sir.

(b) Ministries and Departments were instructed to locate savings to the maximum extent possible to meet any unavoidable increases in expenditure including liability for additional instalments of dearness allowance and bonus sanctioned to Government employees during the year. They were also required to closely monitor the progress of expenditure. Economy instructions issued last year were continued this year also.

हिन्दी अनुवादों आदि के लिए समान वेतन

1715. **श्री अश्विनी कुमार** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के अनेक विभागों/कार्यालयों, विशेषकर डाक-तार और दूर संचार विभाग में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों और वरिष्ठ प्रूफ रीडरों के संवर्ग में समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सभी मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों और वरिष्ठ प्रूफ रीडरों के लिए एक समान वेतनमान लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के पद, मंत्रालयों विभागों तथा सम्बद्ध और अधीन कार्यालयों में विद्यमान हैं। मंत्रालयों

विभागों और उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के अधिकांश पद केन्द्रीय सचिवालय राज भाषा सेवा में शामिल हैं। चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के वरिष्ठ अनुवादकों को 1640-2900 रुपए (पूर्व संशोधित वेतनमान-550-800 रुपए का एक समान वेतन मान दिया गया है। केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा, राजभाषा विभाग के नियंत्रणाधीन है। जो मंत्रालय/ विभाग और सम्बद्ध कार्यालय केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में सम्मिलित नहीं है वे वरिष्ठ अनुवादकों के वर्ग का स्वयं नियंत्रण करते हैं। सभी मंत्रालय और विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों में वरिष्ठ अनुवादकों के संवर्ग का नियंत्रण करते हैं। 550-800 रूपए और 550:900 रुपए के दो वेतनमान उन वरिष्ठ अनुवादकों के पदों के लिए हैं जो केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल नहीं है, चतुर्थ वेतन आयोग ने 550-800 रुपए के वेतनमान को संशोधित करके 1600-2660 रुपए और 550-900 रुपए के वेतनमान को संशोधित करके 1640-2900 रुपए कर दिया है। आयोग ने वरिष्ठ अनुवादकों के पदों के वेतनमान को तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की। आयोग की सिफारिश के अनुसरण में वरिष्ठ अनुवादकों के शेष पदों को 1640-2900 रुपए के वेतनमान में सम्मिलित करके उनके लिए माडल भर्ती नियमों को परिचालित करने पर विचार किया जा रहा है ताकि उनका वेतनमान भी दूसरों के समान हो सके। डाक और दूर संचार विभागों में वरिष्ठ प्रूफ रीडरों के लिए 1320-2040 रुपए प्रतिमास का केवल एक वेतनमान है।

Tax on presumed income

1716. SHRI PARVATHANENI UPPENDRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry has termed the policy of Government of charging tax on presumed income as 'unjustifiable'; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) The point raised by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry is whether there is any justification in presuming a particular rate of profit on the purchase price of any commodity and enforcing the collection of tax at the time of purchase of the commodity.

(b) The Government is of the view that charging of tax on presumed income is justifiable.

Use of Hindi

1717. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have assessed the use of Hindi in the departments under the various Ministries;

(b) whether it is a fact that a number of Government departments and several public sector organisations have failed to implement the policy of use of Hindi in their day-to-day communications; and

(c) whether Government have received any complaints about non-use of Hindi in the Hindustan Paper Corporation Limited, Calcutta?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) Yes, Sir. The assessment is done from time to time.

(b) No, Sir. The Govt. departments and public sector organisations are making earnest efforts to increase the use of Hindi progressively in their day-to-day communications. A number of Government Departments and public sector organisations have,